३. अंग्रेजी सत्ता के परिणाम

प्रस्तुत पाठ में अंग्रेजी सत्ता के भारत पर क्या परिणाम हुए; उसका हम अध्ययन करेंगे ।

त तढश ईस्ट इंतड्या कंपनी की स्थापना : हमने देखा कि भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप की सत्ताएँ भारत के तटों पर किस तरह आ पहुँचीं । पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज; ये सभी सत्ताएँ भारत के बाजार को अपने अधिकार में कर लेने की सत्ता स्पर्धा में उतरी हुई थीं । जब अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने आए; तब भारत में पहले से ही आए हुए पुर्तगालियों ने उनका कठोर विरोध किया । कालांतर में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच मित्रता के संबंध स्थापित हुए और दोनों के बीच का विरोध कम हो गया । परंतु भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की स्पर्धा में अंग्रेजों को फ्रांसीसी, डच और स्थानीय सत्ताधीशों के विरोध का सामना करना पड़ा ?

अं और मराठे : मुंबई अंग्रेजों का पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र था । इसके आस-पास के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने का अंग्रेजों का प्रयास था परंतु इस प्रदेश पर मराठों की बड़ी मजबूत पकड़ थी । माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद की लालसा में आकर उनके चाचा रघुनाथराव ने अंग्रेजों से सहायता माँगी । इस प्रकार मराठों की राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ ।

१७७४ ई. से लेकर १८१८ ई. के बीच मराठा और अंग्रेजों के बीच तीन युद्ध हुए । प्रथम युद्ध में मराठा सरदारों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किया । परिणामतः मराठों की विजय हुई । १७८२ ई. में सालबाई की संधि हुई और अंग्रेज-मराठा के बीच चल रहा यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ ।

सहायक सेना : १७९८ ई. में लॉर्ड वेलस्ली भारत में गवर्नर जनरल के रूप में आया । संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना उसकी नीति थी । इसके लिए उसने अनेक भारतीय सत्ताधीशों के साथ सहायक सेना के समझौते किए । इस समझौते के अनुसार भारतीय सत्ताधीशों को अंग्रेजी सेना की सहायता का आश्वासन दिया गया परंतु इस सहायता के लिए कुछ शर्तें रखी गईं ।

इन शर्तों के अनुसार भारतीय राजाओं को उनके राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी होगी । इस सेना के व्यय हेतु नकद राशि अथवा उतनी आय का प्रदेश कंपनी को देना होगा, भारतीय शासक अन्य सत्ताधीशों के साथ अंग्रेजों की मध्यस्थता से ही संबंध स्थापित करेगा; अपने दरबार में अंग्रेजों का रेजिडेंट (प्रतिनिधि) रखना होगा । भारत के अनेक सत्ताधीशों ने इस संधि को स्वीकारा और अपनी स्वतंत्रता खो बैठे ।

१८०२ ई. में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की । यह संधि वसई की संधि के रूप में प्रसिद्ध है परंतु यह संधि अनेक मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी । फलस्वरूप अंग्रेज और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ । इस विजय के पश्चात अंग्रेजों का मराठी राज्य में हस्तक्षेप बढ़ने लगा । यह हस्तक्षेप बाजीराव द्वितीय को असह्य हुआ । अतः बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की । इस युद्ध में उसकी पराजय हुई । १८१८ ई. में उसने आत्मसमर्पण किया । इस बीच मुगलों की राजधानी प्रत्यक्ष में दौलतराव शिंदे के अधिकार में थी । शिंदे की सेना को पराजित कर जनरल लेक ने मुगल शासक को बंदी बनाया और हिंदुस्तान पर विजय पा ली ।

प्रा िप तसं्ह : पेशवाई का अस्त हुआ फिर भी सातारा के छत्रपति प्रताप सिंह गद्दी पर थे । अंग्रेजों ने छत्रपति प्रताप सिंह के साथ संधि कर ली और ग्रांट डफ नामक अधिकारी को उनके राज्य प्रशासन में सहायता करने हेतु नियुक्त किया परंतु कालांतर में उन्हें

छत्रपती प्रताप सिंह

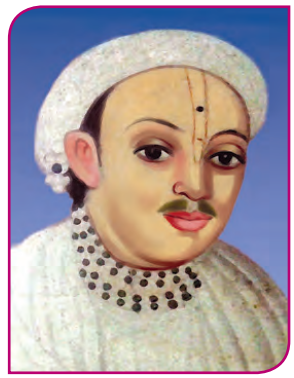

गद्दी से पदच्युत करके काशी में रखा । वहीं पर उनकी १८४७ ई. में मृत्यु हुई ।

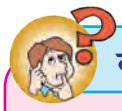

क्या तुम जानते हो ?

छत्रपति प्रताप सिंह ने सातारा शहर में येवतेश्वर मंदिर के पीछे और महादरा में तालाबों का निर्माण करवाया और उन तालाबों का पानी शहर में ले आए । शहर में सड़कें बनवाईं, सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, लड़के-लड़कियाँ संस्कृत-मराठी, अंग्रेजी सीखें; इसके लिए विद्यालय का निर्माण करवाया । वहीं पर एक छापाखाना (प्रेस) खुलवाया और अनेक उपयोगी ग्रंथ छपवाए । १८२७ ई. में उन्होंने राजनीतिविषयक 'सभानीति' नामक एक ग्रंथ लिखकर छपवाया । उन्होंने सातारा से महाबलेश्वर तथा प्रतापगढ़ तक की सड़क बनवाई । वही सड़क आगे महाड़ तक ले जाई गई । छत्रपति प्रताप सिंह प्रतिदिन दैनंदिनी (डायरी) लिखा करते थे ।

छत्रपति प्रताप सिंह के प्रमुख प्रशासक रंगो बापूजी गुप्ते ने इंग्लैंड जाकर इस अन्याय के विरुद्ध गुहार लगाई परंतु न्याय माँगने के उनके प्रयास विफल हुए । आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने उत्तराधिकारी अधिकार (दत्तक विधान) अस्वीकार कर १८४८ ई. में सातारा का राज्य हड़प लिया ।

अं ी सती के भारि पर परणाम

िहरी शासन व्यवस्था : रॉबर्ट क्लाइव ने १७६५ ई. में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की । कंपनी ने राजस्व इकट्ठा करने का कार्य अपने हाथ में रखा तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य बंगाल के नवाब को सौंपा, इसी को 'दोहरी शासन व्यवस्था' कहते हैं ।

दोहरी शासन व्यवस्था के दुष्परिणाम कालांतर में दिखाई देने लगे । सामान्य जनता से कर के रूप में वसूल किया गया पैसा कंपनी के अधिकारियों ने अपनी जेब में दबाया । भारत में व्यापार करने का एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था । अतः इंग्लैंड के कई व्यापारी इस कंपनी के प्रति ईर्ष्या रखते थे । भारत में चल रहे कंपनी के प्रशासन पर इंग्लैंड में आलोचना होने लगी । तब कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने कुछ महत्त्वपूर्ण कानून बनाए ।

पा ारा बनाए गए कानून : १७७३ ई. के रेगूलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को 'गवर्नर जनरल' का पद दिया गया । इस एक्ट के अनुसार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज गवर्नर जनरल बना । उसे मुंबई और मद्रास (चेन्नई) प्रांतों की नीतियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त हुआ । उसकी सहायता करने के लिए चार सदस्यों की समिति का गठन किया गया ।

१७८४ ई. में भारत के विषय में पिट का कानून पारित हुआ । कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था पर पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने हेतु एक स्थायी स्वरूप की नियंत्रण परिषद गठित की गई । इस परिषद को कंपनी द्वारा भारत में चलाई जा रही शासन व्यवस्था के विषय में आदेश देने का अधिकार दिया गया । १८१३ ई., १८३३ ई. और १८५३ ई. में कंपनी की शासन व्यवस्था में फेरबदल करने वाले कानून पार्लियामेंट ने बनाए । इस प्रकार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण आ गया ।

अंग्रेजी सत्ता के आगमन के पीछे-पीछे भारत में नई प्रशासनिक प्रणाली रूढ़ हो गई । प्रशासनिक नौकरतंत्र, सेना, पुलिस बल और न्याय प्रणाली अंग्रेजों के भारत में चलाए जा रहे प्रशासन के प्रमुख आधार स्तंभ थे ।

तन्क्र नौकरि (तसतक्स स सेस) : भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए अंग्रेजों को नौकरतंत्र की आवश्यकता थी । लॉर्ड कार्नवालिस ने नौकरतंत्र का निर्माण करवाया । प्रशासनिक नौकरतंत्र अंग्रेजी शासन व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण घटक बना । कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे; ऐसा उसने नियम बनाया । इसके लिए उसने अधिकारियों के वेतनों में वृद्धि की ।

उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अंग्रेजों के अधिकारवाले प्रदेशों का जिले के अनुसार

विभाजन किया । जिलाधिकारी (कलेक्टर) जिला प्रशासन का प्रमुख था । राजस्व इकट्ठा करवाना, न्याय प्रदान करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना उसके महत्त्वपूर्ण दायित्व थे । अधिकारियों की भरती इंडियन सिविल सर्विसेस (आई.सी.एस.) प्रतियोगिता परीक्षाओं द्‌वारा की जाने लगी ।

सेना और प स बल : भारत में अंग्रेजों के अधिकारवाले प्रदेशों की रक्षा करना, नए प्रदेशों को हथिया लेना और भारत में अंग्रेजों के विरुद्‌ध होने वाले विद्रोह का दमन करना सेना के कार्य थे । देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल का कार्य था ।

न्याय : इंग्लैंड में प्रचलित न्याय प्रणाली के ढर्रे पर अंग्रेजों ने भारत में नई न्याय प्रणाली स्थापित की । प्रत्येक जिले में असैनिकी अर्थात नागरिकों के मुकदमों के लिए दीवानी न्यायालय और फौजदारी (आपराधिक) मुकदमों के लिए न्यायालय स्थापित किए गए । उनके निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए ।

कानून के सम सभी समान (तवतधशासन) : पूर्व समय में भारत में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग कानून प्रचलित थे । न्याय प्रदान करने में जातियों के अनुसार भेदभाव किया जाता था । लार्ड मेकॉले के नेतृत्व में स्थापित की गई विधि समिति ने कानून की संहिता तैयार की । संपूर्ण भारत में एक ही कानून लागू किया । कानून के सम्मुख सभी समान हैं; यह सिद्‌धांत अंग्रेजों ने रूढ़ कर दिया ।

इस प्रणाली में भी कुछ दोष थे । यूरोपीय लोगों के मुकदमे चलाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय थे और विभिन्न कानून थे । नए कानून आम लोगों की समझ से परे थे । न्याय पाना साधारण लोगों के लिए बहुत खर्चीली बात थी । मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहते थे ।

अं की आ क नीतियाँ : प्राचीन समय से भारत पर आक्रमण होते रहे । अनेक आक्रमणकारी भारत में स्थायी रूप में बस गए । वे भारतीय संस्कृति में घुल-मिल गए । यद्‌यपि उन्होंने यहाँ शासन किया; फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए । अंग्रेजों के विषय में ऐसा नहीं हुआ ।

इंग्लैंड आधुनिक राष्ट्र था । औद्‌योगिक क्रांति होने से वहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था रूढ़ हो गई थी । इस व्यवस्था के लिए पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की । परिणामतः इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुए परंतु भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लगा ।

भू-रार स्व (लगान) तवस्यक नीत : अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पूर्व देहात की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी । कृषि और अन्य उद्‌योगों द्‌वारा गाँव की आवश्यकताएँ गाँव में ही पूरी हो जाती थीं। भू-राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था । अंग्रेजों के पूर्व समय में फसलों के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था । फसल अच्छी न आने पर लगान में छूट मिल जाती थी । राजस्व मुख्य रूप से अनाज के स्वरूप में लिया जाता था । यदि लगान अदा करने में विलंब भी हो जाए तब भी किसानों से उनकी भूमि छीन नहीं ली जाती थी ।

आय में वृद्‌धि लाने हेतु अंग्रेजों ने राजस्व प्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए । अंग्रेजों ने भूमिका का मापन करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार लगान का निर्धारण किया । लगान नकद राशि में और निश्चित समय में अदा करने हेतु कड़ाई बरती जाने लगी । नियम बनाया गया कि लगान निर्धारित समय के भीतर अदा न किए जाने पर किसानों की भूमि सरकार द्‌वारा अधिग्रहित (जब्त) कर ली जाएगी । अंग्रेजों की राजस्व इकट्ठा करने की प्रणाली भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग थी । सर्वत्र किसानों का शोषण होता था ।

नई भू-रार स्व व्यवस्था के ि : नई भू-राजस्व व्यवस्था के दुष्प्रभाव ग्रामीण जीवन पर हुए । किसान उन दामों में अपनी फसल बेचने लगे; जिन दामों में लगान भरा जा सकेगा । व्यापारी और आढ़तिये उचित दामों से भी कम मूल्य पर उनकी उपज खरीदने लगे । समय पड़ने पर किसानों को लगान भरने के लिए साहूकार के पास अपने खेत

गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ता था । फलस्वरूप किसान कर्जदार बन गए । कर्ज न लौटाने पर उन्हें अपने खेत बेचने पड़ते थे । सरकार, जमींदार, साहूकार, व्यापारी किसानों का शोषण करते थे ।

कृ का व्यापारीकरण : पहले किसान मुख्यतः खाद्यान्न उगाता था । इस खाद्यान्न का उपयोग किसान घरेलू उपयोग और गाँव की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए करता था । अब अंग्रेज सरकार कपास, नील, तंबाकू, चाय जैसी नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने लगी । खाद्यान्नों की उपज लेने की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त करा देने वाली व्यापारिक अथवा नकदी फसलें लेने पर बल दिया जाने लगा । इस प्रक्रिया को 'कृषि का व्यापारीकरण' कहते हैं ।

अकाल : १८६० ई. से १९०० ई. के बीच भारत में बड़ी मात्रा में अकाल की स्थितियाँ उत्पन्न हुईं परंतु अंग्रेज शासकों ने अकाल निवारण हेतु पर्याप्त प्रयास नहीं किए । साथ ही; जलापूर्ति की योजनाओं पर पर्याप्त व्यय भी नहीं किया ।

परिवहन एवं संचार व्यवस्था सुधार : अंग्रेजों ने व्यापार वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत में परिवहन और संचार की आधुनिक सुविधाएँ निर्माण कीं । उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाले राजमार्ग का निर्माण करवाया । १८५३ ई. में मुंबई-ठाणे रेल मार्ग पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी । इसी वर्ष टेलीग्राम यंत्र द्वारा संदेश भेजने की व्यवस्था अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ की । इस व्यवस्था द्वारा भारत के प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान एक-दूसरे के साथ जोड़े गए । इसी भाँति; अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था भी प्रारंभ की ।

मुंबई-ठाणे रेल (१८५३)

इन सभी सुधारों के भारतीय समाज जीवन पर दूरगामी परिणाम हुए । देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क बढ़ा । परिणामतः उनके बीच एकता की भावना में वृद्धि होने में सहयोग मिला ।

भार् के पुरान उद् का ास : भारत से इंग्लैंड जाने वाले माल पर अंग्रेज सरकार जबरदस्त कर वसूल करती थी । इसके विपरीत इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लिया जाता था । इस तरह; इंग्लैंड से आने वाला माल यंत्र द्वारा निर्मित होता था । परिणामस्वरूप उस माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था । ऐसे सस्ते माल के साथ प्रतिद्वंद्विता करना भारतीय कारीगरों को कठिन सिद्ध हुआ । परिणामतः भारत के पारंपरिक उद्योग-धंधे बंद हो गए और अनेक श्रमिक बेरोजगार बन गए ।

भार् नए उद् का कास : अंग्रेज सरकार का समर्थन, प्रबंधन का अनुभव और पूँजी जैसी बातों का अभाव होने से भारतीय उद्योजक बड़ी संख्या में आगे नहीं आ पाए । फिर भी ऐसी अनेक बाधाओं पर विजय पाकर कई भारतीयों ने उद्योगों का निर्माण किया ।

१८५३ ई. में कावसजी नानाभौय दावर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल शुरू की । १८५५ ई. में बंगाल के रिश्रा में पटसन की पहली मिल प्रारंभ हुई । १९०७ ई. में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया ।

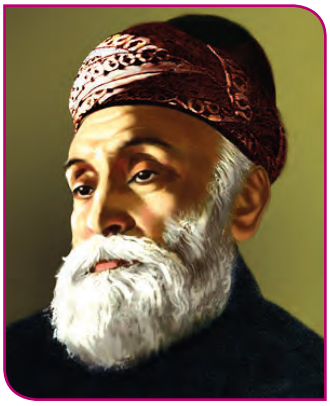

जमशेदजी टाटा

भारत में कोयला, खनिज-धातुएँ, चीनी, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों जैसे उद्योगों का भी प्रारंभ हुआ ।

सामातरक और सांस्क्तकि परणाम : उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावाद, विचारवाद, लोकतंत्र, उदारतावाद जैसे नए मूल्यों पर आधारित नए युग का अवतरण हुआ था । पश्चिमी विश्व के इस परिवर्तन की प्रतिक्रिया भारत में होना स्वाभाविक था । अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए भारतीय समाज को भली-भाँति जानना आवश्यक था । इसके लिए उन्होंने यहाँ की परंपराएँ, इतिहास, साहित्य, कलाएँ तथा यहाँ का संगीत, पशु-पक्षी का भी अध्ययन करना प्रारंभ किया । १७८४ ई. में अंग्रेज अधिकारी विलियम जोंस ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' संस्था की स्थापना की । जर्मन विचारक मैक्समूलर भारतीय धर्म, भाषा और इतिहास का गहन अध्येता था । इन उदाहरणों द्वारा हमें भी अपने धर्म, इतिहास और परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए; यह बोध नवशिक्षित भारतीयों में उत्पन्न होने लगा ।

अंग्रेजों ने भारत में नए कानून बनाए । १८२९ ई. में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया । १८५६ ई. में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया । ये कानून धर्म सुधार की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए ।

प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी । लॉर्ड मेकॉले की सिफारिश के अनुसार १८३५ ई. में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ । नई शिक्षा द्वारा नये पश्चिमी विचार, आधुनिक सुधार, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान से भारतीयों को परिचित कराया गया । १८५७ ई. में कोलकाता, मुंबई, मद्रास (चेन्नई) में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई । पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्ग ने भारत में सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन का नेतृत्व किया ।

स्वाध्याय

१. तिए गए तक्कल्प से उतचा तिक्कल्प चनकर कथन पन: तर्लाि ।

(१) पुर्तगाली, ... , फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत का बाजार अपने अधिकार में कर लेने के लिए सत्ता की होड़ में उतरे ।

(अ) ऑस्ट्रियन (ब) डच
(क) जर्मन (ड) स्वीडीश

(२) १८०२ ई. में .... अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली ।

(अ) बाजीराव प्रथम (ब) सवाई माधवराव
(क) पेशवा नानासाहब (ड) बाजीराव द्वितीय

(३) जमशेदजी टाटा ने .... में टाटा आयर्न एंड स्टील कंपनी का इस्पात निर्माण का कारखाना स्थापित किया ।

(अ) मुंबई (ब) कोलकाता
(क) जमशेदपुर (ड) दिल्ली

२. तन्म संकल्म को स्म करो ।

(१) प्रशासनिक नौकरतंत्र
(२) कृषि का व्यापारीकरण
(३) अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ

३. तन्म को कारणसतह स्म करो ।

(१) भारत के किसान कर्जदार बन गए ।
(२) भारत के पुराने उद्योग-धंधों का ह्रास हो गया ।

४. पाठ के आधार पर तन्म सारणी पू करो ।

व्यक्ति	कार्य
लॉर्ड कॉर्नवालिस	....
....	सती प्रथा पर रोक लगाने का कानून बनाया ।
लॉर्ड डलहौजी	....
....	'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' की स्थापना ।

अंग्रेजों द्वारा प्रशासन, शिक्षा, परिवहन और संचार व्यवस्था में किए गए सुधारों की चित्र सहित जानकारी तैयार करो ।

9A33LH